Default in Wages and Salaries in P.S.Us.

1470. SHRI GURUDAS DAS GUPTA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether Government are aw are that there has been delay or de fault in payment of wages and sala-vies in a number of public sector undertakings in the country; and

(b.) if so, what steps Government propose to take in this regard?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) Yes Sir.

(b) As and when such instances are brought to the notice of the Go. vetnment urgent remedial measures are suggested to the PSE by the administrative Ministry concerned.

Utilisation of Rupee Repayment Fund for industrial projects

1471. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state;

(a) whether it is a fact that India and Russia have recently agreed to utilise aportion of the Rupee Repayment Fund to finance construction and modernisation of industrial projects in India and also to make conetribution to the equity of Indo-Russian joint ventures operating in India; and

(b) if so, the details thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI) (a) and (b) During the Prime Minister's visit to Moscow from 29th June to 2nd July, 1994, the questions relating to repayment of outstanding debt by India to Russia were discussed. It was agreed that the rupee balances due to Russia on account of debt repayment could be used to invest in agreed projects in India. The rupee funds can also be used to import machinery and equipment for modernisation of projects in Russia. However, no concrete proposals have yet been received, and the detailed modalities are yet to be agreed upon between the two sides.

कच्छ में उद्योगों की स्थापना के लिए समिति

1472. श्रीमती चन्द्रिका अमिन दन जैन: क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कच्छ के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापति करने और जन्हें बढ़ावा देने के लिए कोई समिति गठित की है;

(ख) सरकार द्वारा इस क्षेत्र, के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगिक क्रान्ति लाने और इस क्षेत्र के बेरोजगार युवाओं को स्व-रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) चालू वित्तीय वर्ष के बजट में इस योजना के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरूणाचलम) : ('क) जी, नहीं।

(ख) यह राज्य सरकारों का उत्तर-दायित्व है कि आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जाएं, ताकि ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में उद्योग स्थापित किये जा सकें। शिक्षित बेरोजगार युवाओं की स्व-रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिये पूरे देश में शिक्षित बेरोजगार युवाओं के लिए प्राधनमंत्री की रोजगार योजना कार्यान्वित की जा रही है। इसके अलावा, खादी और ग्रामोद्योग आयोग कच्छ के ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों सहित देश में ग्रामीण उद्योगों के संवर्धन और रोजगार पैदा करने के लिए कई योजनायें भी कार्यान्वित कर रहा है।

(ग) चालू वित्तीय वर्ष (1994-95) के बजट में प्रधान मंत्री की रोजगार योजना के लिये 145 करोड़ रु० तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग की योजनाओं के लिये 214 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है।

एच० एम० टी० को निजी क्षेत्र के साथ संयुक्त उद्यम स्थापित करने के लिए अनुमति का दिया जाना

1473. श्री सोम पाल:
श्री सरदा महतो:
डा० नौनिहाल सिंह:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड को उत्पादन और विपणन क्रियाकलापों के लिये देश में और विदेश में उसकी विभिन्न इकाइयों को निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर संयुक्त उद्यम स्थापित करने की अनुमति दे दी है अथवा देने का विचार रखती है ;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसे मामलों में हिन्दुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड ने सहयोग करने के संबंध में किन-किन कम्पनियों के साथ विचार विमर्श किया है अथवा निर्णय लिया है।

(ग) इस संबंध में अब तक हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है और इसकी वित्तीय और उत्पादन क्षमता संबंधी स्थिति का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) इस नीति से क्या लाभ प्राप्त होने की संभावना है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (घ) : एच० एम० टी० की प्रौद्योगिकी एवं पूंजी आदि की भावी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, सरकार ने कम्पनी के अलग-अलग व्यवसाय समूहों को अन्तर्राष्ट्रीय भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम कम्पनियों में परिवर्तित करने के लिये सिद्धांतरूप में अनुमति दी है। कम्पनी विभिन्न संभावनाओं का पता लगा रही है। अधिक ब्यौरा बताना इस समय एच.एम.टी. के वाणिज्यिक हित में नहीं होगा।

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा उठाए गए घाटे के कारण

1474. श्री जगेश्वर यादव:

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सार्वजनिक क्षेत्र के अधिकांश उद्यमों में उनके शुरू किये जाने के कुछ समय के बाद ही घाटा होना प्रारम्भ हो जाता है ;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा ऐसे रुग्ण उद्यमों की समस्याओं को हल करने के लिये उसी समय प्रयास न किये जाने के क्या कारण हैं, जिससे कि उनको निरन्तर होने वाले घाटे को रोका जा सके ;

(ग) क्या सार्वजनिक क्षेत्र के इन उद्यमों में अकुशल अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक की नियुक्ति का किया जाना और संसाधनों का अनुचित प्रयोग किया जाना भी इन उद्यमों के रुग्ण होने के प्रमुख कारण हैं ;

(घ) यदि हां, तो सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के क्रियाकलापों पर निगरानी रखने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ; और

(ङ) सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के ऐसे रुग्ण उद्यमों को पुनरुज्जीवित करने के लिये क्या कदम उठाए हैं और ये कदम कितने प्रभावशाली सिद्ध हुए हैं ?